और... एक शे'र

आज तो मिल के भी जैसे न मिले हों तुझसे
चौंक उठते थे कभी तेरी मुलाक़ात से हम

-जां निसार अख़्तर

लोकमत समाचार
तमसो मा ज्योतिर्गमय

मित्रता आनंद को दुगुना और दुख को आधा कर देती है.
■ अज्ञात

संपादकीय

खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या चिंतनीय

बाजार में हर पांचवें खाद्य पदार्थ के मिलावटी होने की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा दी गई जानकारी देशवासियों के स्वास्थ्य के लिहाज से चिंता में डालने वाली है. स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा सदस्य एवं लोकमत पत्र समूह के एडिटोरियल बोर्ड के चेयरमैन विजय दर्डा के सवाल के जवाब में राज्यसभा को बताया कि वर्ष 2014-15 के दौरान देशभर से पैक्ड खाद्य पदार्थों के 68,197 नमूने लिए गए. इनमें से 60,548 की जांच कराई गई. जांच से पता चला कि 12,077 नमूने या तो मिलावटी थे या उन पर सही सूचनाएं नहीं दी गई थीं. खास बात यह है कि इनमें पैकेट बंद दूध, पानी और मिठाइयां भी शामिल हैं. खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की शुद्धता संदिग्ध होने के कारण लोग महंगा होने के बावजूद पैकेट बंद खाद्य पदार्थ लेना पसंद करते हैं. अब उनमें भी अगर मिलावट की यह हालत है तो नागरिकों के सामने क्या विकल्प बचता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के आंकड़ों के अनुसार 2682 मामलों में आर्थिक दंड लगाकर 10.64 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वसूली जा चुकी है. सवाल यह है कि नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर क्या सिर्फ जुर्माना लगा देना ही पर्याप्त है. देश में बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं. छोटे-छोटे बच्चे तक गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होने लगे हैं. शरीर को स्वस्थ रखने में खान-पान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है. कहावत है 'जैसा खावे अन्न, वैसा होवे मन'. अगर अन्न ही शुद्ध नहीं रहेगा तो तन और मन कैसे स्वस्थ रहेंगे? किसी भी खाद्य पदार्थ में कोई रासायनिक या बाहरी अन्य चीज मिलाने से उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है तो उस खाद्य पदार्थ को मिलावटयुक्त पदार्थ कहा जाता है. कुछ मिलावटी चीजों के असर तत्काल दिख जाते हैं लेकिन अनेक मिलावटी वस्तुओं के दुष्परिणाम लंबे समय बाद देखने में आते हैं. हमें पता भी नहीं चल पाता कि किस वस्तु में मिलावट का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है. देशवासियों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों को कानून के अनुसार तो कड़ा दंड मिलना ही चाहिए, इस बारे में जनजागृति भी जरूरी है. खाद्य पदार्थों में मिलावट की आसानी से जांच कैसे की जाए, इसके बारे में व्यापक मुहिम चलाकर लोगों को जानकारी देनी चाहिए. मिलावट करने वालों के बारे में जनता द्वारा सूचना देने पर तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था होनी चाहिए. दंड का भय और जनजागृति, दोनों के तालमेल से ही देश की इस गंभीर होती जा रही समस्या पर काबू पाया जा सकता है.

डाका

बारात दरवाजे तक पहुंची ही थी कि लड़के के भाइयों ने तीस-तीस रुपए के बमों की धमाकेदार आतिशबाजी शुरू कर दी. नशे में धुत्त बारातियों के तेवर देखकर लड़की के पिता ब्रजनाथजी का पसीना छूट गया और वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए.

उसी गांव में उसी समय थोड़ी ही दूर सेठ मदन लाल की हवेली पर डाकुओं ने दो-चार हवाई फायर किए. सेठ पसीना-पसीना कांपते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए.

लघुकथा

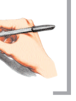

कमल चोपड़ा

गांव में डाका पड़ने की खबर शादी वाले घर भी पहुंच चुकी थी. बारातियों में भी हड़बड़ी मच गई. ''पंडित जी जल्दी करो.... रघु, सत्तू, विजय, जल्दी-जल्दी दहेज का सामान बांधो...बर्तन-सर्तन जो कुछ भी है, छिटपुट सभी समेटो... गठरियों में ही बांध लो और निकल चलो...''

उधर डाकू सरदार चीख रहा था, ''सेठ! नगदी, जेवर, बर्तन अपने आप जल्दी से निकाल दे!'' और सेठजी कांपते हुए आज्ञा का पालन करने लगे.

''बधाई हो ब्रजनाथ जी! फेरे भी हो गए ... अब जरा जेवर और नगदी भी जल्दी से दीजिए. समय बड़ा खराब है. हमें अंधेरा रहते ही तारों की छांव में ही निकल पड़ना चाहिए!''

उधर डाकू सरदार सिंह कह रहा था, ''साथियो! इससे पहले कि कोई मुसीबत खड़ी हो, हमें सुबह होने से पहले अंधेरे में ही निकल जाना चाहिए .....!''

डाकुओं ने जाते हुए फिर से हवाई फायर किए. उनके जाते ही सेठ जी व उनका लुटा-पुटा परिवार रोने लगा.

डोली के जाते ही ब्रजनाथ व उनके घर वाले खाली घर को देख सिसकने लगे. जमा-जोड़ और 'लक्ष्मी' सब-कुछ चला गया.

थोड़ी ही देर में गांव में पुलिस आ गई. लेकिन न जाने क्यों पुलिस का एक भी आदमी ब्रजनाथजी के घर नहीं आया.

पुरानी दीवारों पर नई पुताई

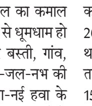

आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

यह राजनीतिक कौशल का कमाल है. देश-विदेश में इस तरह से धूमधाम हो रही है कि भारत की हर बस्ती, गांव, इमारत, टेक्नोलॉजी, थल-जल-नभ की उथल-पुथल तक नए रंग-नई हवा के अनुसार चलने लगी है. सामान्यतः लोगों की याददाश्त सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को दर्ज नहीं कर पाती. इसलिए 'स्किल इंडिया'-'डिजिटल इंडिया', 'स्वच्छ भारत' और 'हर घर में शौचालय' के नव घोषित कार्यक्रमों को भाजपा सरकार की अपनी नई सोच के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. यों कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारों ने न तो ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से किया और न ही उनका प्रचार-प्रसार सही तरीके से हुआ. लेकिन नई सरकार और मीडिया को कम-से-कम अच्छे काम की शुरुआत करने वाले शीर्ष नेताओं को श्रेय देते हुए याद करना चाहिए.

मेरी नजर में 'स्किल इंडिया' यानी स्किल डेवलपमेंट योजना भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आर्थिक भविष्य बनाने वाली है. मोदी सरकार ने इसके नाम पर एक नया मंत्रालय अवश्य बना दिया, लेकिन भारत में कुशल कारीगर तैयार करने के उद्देश्य से 6 जुलाई 2009 को संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट पेश करते हुए 495 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की थी. अगले साल इस काम के लिए एक हजार करोड़ और फिर 2012 तक 2500 करोड़ का प्रावधान हो गया. नेशनल स्किल डेवलपमेंट कार्पोरेशन बनाने का फैसला तो 2008-2009 के बजट भाषण में सुना दिया गया था. प्रणब मुखर्जी ने उस समय ही 2022 तक भारत में कौशल प्रशिक्षण से करीब 15 करोड़ लोगों को रोजी-रोटी कमाने लायक बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया था. श्री मुखर्जी अब राष्ट्रपति पद पर आसीन हैं. अब वह स्वयं सार्वजनिक रूप से इस बात का ढिंढोरा नहीं पीट सकते कि 'स्किल इंडिया' का काम तो पांच साल से चल रहा था. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संभवतः अब यह भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि उनके सत्ताकाल में ही वित्त मंत्री बने पी. चिदंबरम ने 2013 में स्किल डेवलपमेंट के लिए विश्व बैंक से चार सौ करोड़ रुपए लेने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. ए. राजा ही नहीं पी. चिदंबरम भी अपने मंत्रालय में मनमानी करते रहे थे. कांग्रेस राज की गलतियों की सजा ऐसे सभी नेताओं को मिली.

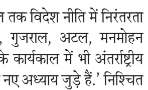

एक साल का रवैया यही दिखाता है कि सरकार की नई स्याही से लिखी जा रही फाइलों में कूपमंडूकता ही अधिक दर्ज हो रही है.

मोदी राज में छवि चमकाने के प्रयास पराकाष्ठा पर हैं. पिछले दिनों 'मोदी की दुनिया' पुस्तक के लोकार्पण में भारत के विदेश सचिव सहित कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद थीं. अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ की पुस्तक में महत्वपूर्ण लेख भी संकलित हैं. लेकिन प्रारंभिक वक्तव्य में प्रकाशन के सहयोगी एक सुशिक्षित संपन्न वक्ता ने ध्यान दिलाया कि 'महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वर्ष की विदेश यात्राओं से दुनिया को पता चल सका कि भारत की कोई विदेश नीति भी है.' बाद में पूर्व विदेश सचिव श्यामशरण ने व्यंग्यात्मक लहजे में इस बात को दोहराया और फिर बताया कि 'नेहरू से मोदी काल तक विदेश नीति में निरंतरता है. इंदिरा, गुजराल, अटल, मनमोहन सरकारों के कार्यकाल में भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नए अध्याय जुड़े हैं.' निश्चित रूप से इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि पंचशील, गुट निरपेक्ष देशों के संगठन, दक्षिण एशियाई देशों के संगठन के माध्यम से पिछले 60 वर्षों में भारत ने विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

मजेदार बात यह है कि कौशल प्रशिक्षण के लिए मोदी सरकार अब 20 लाख का लक्ष्य बताकर अपनी पीठ थपथपा रही है. राजनीतिक खींचातानी, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार और औद्योगिक विकास में मंदी के कारण देश में हर साल लगभग 55 लाख लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा है, जबकि हर साल एक करोड़ बीस लाख लोग रोजगार की तलाश में भटकने निकलते हैं. मुझे याद है- दो दशक पहले गुजरात में टेक्सटाइल मिलों में लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ था.

बहरहाल, बात शुरू हुई थी - दीवारों पर नई पुताई से. तो जरा रिकार्ड देख लें. बहुत कुछ जानकारी नई सरकार आने से पहले 'डिजिटल' हो चुकी है. ग्रामीण विकास के लिए कई हजार करोड़ रुपयों का प्रावधान पिछले 10 वर्षों के बजट में दिख सकता है. मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस वर्ष के अंत तक नई शिक्षा नीति की क्रांतिकारी घोषणा करने के बयान दिए हैं. लेकिन उनसे अधिक अनुभवी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर ने क्या अपने कार्यकाल में शिक्षा-व्यवस्था बिगाड़ दी थी? शिक्षा-नीति में बदलाव के दावे पिछले 50 वर्षों में हर शिक्षा मंत्री ने किए. संभव है स्मृति ईरानी कुछ नए और अच्छे बदलाव भी कर दें. लेकिन एक साल का रवैया यही दिखाता है कि सरकार की नई स्याही से लिखी जा रही फाइलों में कूपमंडूकता ही अधिक दर्ज हो रही है. इतिहास को बदलने व नेहरू-गांधी का नाम हटाने से स्कूल-कॉलेजों की स्थिति कैसे आदर्श हो जाएगी? जरूरत है- पुरानी दीवारों, पुरानी नींव को सुरक्षित रख भारत के नव-निर्माण की संतुलित और दूरगामी हितों की रक्षा करने वाली नीतियों की.

संसद और हंगामा

नजरिया उर्दू प्रेस का

■ राजश्री यादव

संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है. उर्दू मीडिया ने भी इसके हंगामाखेज होने की बात कही है. **'इन्कलाब डेली'** मुंबई ने लिखा है संसद की कार्यवाही के साथ हंगामे का तसव्वुर इस तरह जुड़ गया है कि दोनों एक-दूसरे के पूरक होकर रह गए हैं. एक जमाना था, जब हंगामा कभी-कभी हुआ करता था. अब कभी-कभी नहीं होता. इसकी एक वजह सुर्खियों में रहने की ख्वाहिश या सुर्खियों में आने की कोशिश भी है. अहले सियासत को हंगामे की इतनी आदत हो गई है कि वो सुर्खियों में जगह पाने के बहाने ढूंढ़ती रहती है. इसे सियासी 'डिमांड' और 'सप्लाई' की सूरत-ए- हाल में भी देखा जा सकता है. अहले सियासत का नुक्त -ए-नजरिया शायद ये है कि जब तक 'डिमांड' को पूरा करवाने के लिए लिए धरना, प्रदर्शन और हंगामा न किया जाए कोई असर नहीं होता.

एक जमाना था, जब हंगामा कभी-कभी हुआ करता था. अब कभी-कभी नहीं होता.

'मुंसिफ डेली' हैदराबाद ने लिखा है बड़बोलापन अक्सर इंसान को पशेमां कर देता है, क्योंकि जोश में अमूमन ये ख्याल नहीं रहता है कि क्या कहा जा रहा है और बाद में उसका नतीजा क्या होगा, और यही बात परेशानी और पशेमानी का कारण बन जाती है. भाजपा के कई नेता और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अपनी ऐसी लफ्फाजी का शिकार हो गए हैं और अपने वादों के जाल में ऐसे उलझ गए हैं कि न निकलते बन पा रहा है न सुलझाते. चुनावों के दौरान भाजपा ने केंद्र की सत्ता में आने के लिए हर तरह का वादा कर लिया. ये भी नहीं देखा कि जो वादा किया है वो काबिले अमल है भी या नहीं. बल्कि सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की खातिर वादे पर वादे करते गए. और आज वही वादे पार्टी और विशेषकर नरेंद्र मोदी के गले की हड्डी बन गए हैं, जिसे न निगलते बन रहा है न उगलते. अखबार ने आगे लिखा है मोदी सरकार ये नहीं जानती देश की जनता उन तमाम वादों का हिसाब जरूर मांगेगी क्योंकि अब वो जाग गई है और अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना जानती है.

'सहाफत डेली' मुंबई ने लिखा है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया है कि उन्होंने इस पार्टी (भाजपा) को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है. उनके मुताबिक भारत में भाजपा के सदस्यों की तादाद 11 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है. अखबार ने लिखा है किसी भी पार्टी के नेता को इस तरह का दावा बहुत सोच समझकर करना चाहिए, जो अमित शाह ने किया है. रही ये बात कि भाजपा के सदस्यों की संख्या 11 करोड़ से ज्यादा हो गई है तो सवाल ये पैदा होता है कि उन 11 करोड़ सदस्यों की हैसियत पार्टी में क्या होगी. वो सिर्फ भीड़ जमा करने के काम आएगी या उनका कोई और अस्तित्व भी होगा, अहमियत भी होगी.

और अंत में...

कुछ तुझे भी खबर है/ओ सोने वाले नाज से/मेरी रातें लुट गईं/नींदें परेशां हो गईं

(साभार 'डेली रौशनी' श्रीनगर)

नजर के पार

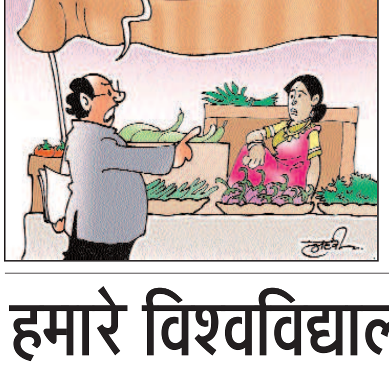
बगैर डॉक्टर की पर्ची के सब्जियां नहीं बेचोगे...सभी में ड्रग है!

राजनीतिक सुधारों की जरूरत

गुरचरण दास
वरिष्ठ पत्रकार

हमारे गणराज्य के साथ कुछ बहुत गलत हो गया है. संसद के हाल ही में शुरू हुए मानसून सत्र पर अशुभ बादल मंडरा रहे हैं. संसद सदस्यों का हमारे आर्थिक सुधारों की नाजुक प्रकृति के साथ गहरा संबंध होना चाहिए, लेकिन विपक्षी सांसद जहां संसद को बाधित करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं सत्तापक्ष के सांसद खरगोश की तरह डरकर भाग रहे हैं और भूल गए हैं कि वे क्यों चुने गए थे.

संसद के अवकाश के दौरान एक सांसद की कार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक बच्ची मारी गई, एक मंत्री ने व्यापमं घोटाले की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार की मौत को 'मूर्खतापूर्ण मुद्दा' कहा, एक राजनेता ने चेन्नई मेट्रो में एक यात्री को थप्पड़ जड़ा और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के इशारे पर एक असुविधा पैदा करने वाले पत्रकार को जला दिया गया. इस बीच राजनीतिक वर्ग के बाकी लोग अपने पसंदीदा धारावाहिक 'ललितगेट' के ताजा प्रकरण को देखने के लिए लगभग तीन सप्ताह तक खामोश उत्साह के साथ अपने टीवी सेट से चिपके रहे. इस धारावाहिक के निर्देशक, पटकथा लेखक और नायक निश्चित रूप से ललित मोदी थे. धारावाहिक अभी खत्म नहीं हुआ था, किंतु इसी बीच इससे भी ज्यादा गंभीर और भयावह व्यापमं घोटाला आगे निकल गया, जिसने भाजपा की प्रतिष्ठा को अधिक नुकसान पहुंचाया. कांग्रेस ने सत्तारूढ़ पार्टी के संबंधित मंत्रियों के इस्तीफे की मांग करते हुए संसद का मानसून सत्र नहीं चलने देने की धमकी दी है. किंतु भाजपा के नेताओं की नजरें बिहार चुनाव और इस पर हैं कि कैसे क्षति को नियंत्रित करें.

निश्चित रूप से भारत बेहतर राजनीति का हकदार है. पहला, देश लगातार चुनावी मोड़ पर है, और इससे महत्वपूर्ण सुधारों तथा कार्यपालिका के फैसलों में देरी हुई है. बजाय इस बात पर बहस करने के देश में बुनियादी ढांचे का निर्माण कैसे किया जाए अथवा व्यापार को आसान करने के लिए लालफीताशाही कैसे खत्म की जाए, भाजपा का नेतृत्व केवल बिहार चुनाव से पहले ललितगेट और व्यापमं घोटाले से हुई क्षति को नियंत्रित करने के बारे में सोच रहा है. दूसरा, विपक्ष को संसद को बाधित करने और देश के एजेंडे को डुबाने के लिए सक्षम नहीं होना चाहिए. भाजपा ने ऐसा पिछली बार किया था और अब कांग्रेस ने जैसे को तैसा का वादा किया है. जनता की किसी को फिक्र नहीं है - जीएसटी लाने में देरी होने, भूमि अधिग्रहण कानून लाने या बेरोजगार युवाओं के बारे में किसी को परवाह नहीं है. निराश होकर हाथ मलने की बजाय हम नागरिकों को अपने जनप्रतिनिधियों से मांग करनी चाहिए कि वे संसद और सरकार दोनों के बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए कुछ सरल राजनीतिक सुधारों को लागू करें. दोनों सदनों के स्पीकरों को हंगामा करनेवाले सदस्यों को सदन से बाहर करने के लिए अपनी उन शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, जो उनके पास पहले से ही हैं. दूसरा, हमारे सांसदों को ज्यादा समय तक काम करना चाहिए. भारतीय संसद की बैठक साल में सिर्फ 67 दिन ही क्यों हो, जबकि ब्रिटेन में यह 150 दिन तथा अमेरिका में 200 दिन होती है? हमारा मानसून सत्र सिर्फ तीन हफ्ते का ही क्यों हो, तीन महीने का क्यों नहीं?

समय आ गया है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को याद दिलाएं कि हमने उन्हें क्यों चुना है. उनसे काम की अपेक्षा की जाती है, जनता का समय और पैसा बर्बाद करने की नहीं.

तीसरा, भारत को निश्चित अवधि के चुनावों को अपनाना चाहिए, जैसा कि ब्रिटेन में अभी किया गया है और अन्य लोकतांत्रिक देशों में लंबे समय से चला आ रहा है. इससे निर्वाचित सरकार को अगले चुनाव के बारे में चिंता किए बिना कार्य करने की शक्ति मिलेगी. चौथे सुधार के रूप में 'अविश्वास प्रस्ताव' की जगह 'अविश्वास के लिए, रचनात्मक मतदान' लाया जा सकता है जैसा कि जर्मनी में है. इसका मतलब है कि सरकार आप तभी गिरा सकते हैं जब आपके पास उसका विकल्प हो.

अंत में, एक सफल लोकतंत्र लोगों की बदलती जरूरतों के साथ दैनिक प्रदर्शन के आधार पर विकसित होता है. समय आ गया है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को याद दिलाएं कि हमने उन्हें क्यों चुना है. उनसे काम की अपेक्षा की जाती है, जनता का समय और पैसा बर्बाद करने की नहीं.

हमारे विश्वविद्यालय फिसड्डी क्यों हैं?

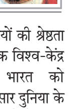

वेद प्रताप वैदिक
वरिष्ठ पत्रकार

दुनिया के विश्वविद्यालयों की श्रेष्ठता का मूल्यांकन करनेवाले एक विश्व-केंद्र का ताजा मूल्यांकन भारत को चैंकानेवाला है. उसके अनुसार दुनिया के पहले 340 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में भारत का एक विश्वविद्यालय भी नहीं है. 341 वें नंबर पर है, दिल्ली का 'इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी'. 379 नंबर पर है, दिल्ली विश्वविद्यालय और फिर हमारे कई नामी-गिरामी विश्वविद्यालयों का नंबर 400, 500 या 600 पर जाकर टिकता है. क्या वजह है कि हमारा देश पढ़ाई-लिखाई में इतना पिछड़ा हुआ है? ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय अमेरिका में हैं. वे यूरोप में तो हैं ही, चीन और जापान में भी हैं. इजराइल, द. कोरिया, बेल्जियम, स्पेन और स्विट्जरलैंड जैसे छोटे-छोटे देशों में भी हैं और वे भारत से बहुत आगे हैं.

हमारे विश्वविद्यालय इतने फिसड्डी क्यों हैं? इस प्रश्न के जवाब में आईआईटी कानपुर के चेयरमैन ने यह कहकर अपनी बला टाली कि उन देशों के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय 500-600 साल पुराने हैं और उनका बजट करोड़ों डॉलर का होता है. ये दोनों तर्क बिल्कुल बोदे हैं. दुनिया के सबसे ज्यादा श्रेष्ठ विश्वविद्यालय अमेरिका में हैं लेकिन स्वयं अमेरिका सवा दो सौ साल पुराना देश है. जहां तक पुराने होने का प्रश्न है, भारत के विश्वविद्यालयों की हजारों साल पुरानी परंपरा है. भारत के जिन नए विश्वविद्यालयों की हम यहां चर्चा कर रहे हैं, वे भी डेढ़ सौ साल पुराने हैं लेकिन असली सवाल यह है कि उनमें पढ़ाया क्या जाता है? अंग्रेजों ने कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में जो तीन विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित किए थे, जरा उनका पाठ्यक्रम उठाकर देखिए. उनका सबसे ज्यादा जोर 'अंग्रेजी भाषा, साहित्य और धर्म-विद्या' पढ़ाने पर था. वे दर्शन और तर्क-विद्या नहीं पढ़ाते थे. वे विज्ञान और गणित नहीं पढ़ाते थे. ऐसी परंपरा में से मौलिकता का जन्म कैसे हो सकता था? अब हमारे लगभग ढाई सौ विश्वविद्यालय में लगभग सभी विषय पढ़ाए जाते हैं लेकिन ढर्रा वही है, जो अंग्रेज महाप्रभुओं ने हम पर लादा था. इसलिए हमारे वि.वि. फिसड्डी हैं. एक बात और. पश्चिम में विश्वविद्यालयीन शिक्षा महंगी है और उसमें वही युवक जाते हैं, जिनकी रुचि और क्षमता है. अपने यहां तो डिग्री और नौकरी का लालच ही विश्वविद्यालय को ठसाठस भर देता है. वे छात्र मौलिक चिंतन और वैज्ञानिक आविष्कार क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? इसके अलावा हमारे विश्वविद्यालयों पर अनिवार्य अंग्रेजी और अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई का ग्रहण लगा हुआ है. दुनिया का कोई श्री श्रेष्ठ विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है, जहां विदेशी भाषा या विदेशी भाषा का माध्यम अनिवार्य हो. भारत में अंग्रेजी के कारण हमारा देश नकलचियों का देश बन गया है. हम विदेशियों की नकल करके रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन और यहां तक कि हवाई जहाज भी बना लेते हैं लेकिन आप जरा बताइए कि हमारे विश्वविद्यालयों ने दुनिया को कौन-सा मौलिक चिंतन या मौलिक आविष्कार करके दिया है?

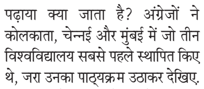

तोल बोल

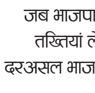

भाजपा के साथ मैं करीब साढ़े सात साल तक रहा, लेकिन उसकी जहरीली प्रवृत्ति का असर मुझ पर नहीं पड़ा.

■ **नीतीश कुमार**, मुख्यमंत्री, बिहार

जब भाजपा विपक्ष में थी तो उसके सदस्य खुद तख्तियां लेकर अपना विरोध व्यक्त करते थे. दरअसल भाजपा ने ही हमें यह रास्ता दिखाया है.

■ **मल्लिकार्जुन खड़गे**, कांग्रेस नेता

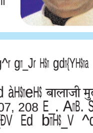

gñWmnH$ gnmXH$:
ñd. Odmhabmb XS>m
M`a_Z, E[S>Q>m{a`b ~moS>:
{dO`> XS>m
E{S>Q>a-BZ-Mr\$:
amOoÐ XS>m
gnmXH : {dH$mg {_l★
★ nr. Ama. ~r. H$mZZ H$ AZgma gnU gmMmaH$s` Xm{`Ëd H$ {bE {Oå_Xma.

© लोकमत समाचार _ àH$m{eV g^r gm_J«r H$m gdm©{YH$ma bmoH$_V _r{S>`m àm`dQ> {b. H$ nmg gw[aj V h.
bmoH$_V _r{S>`m àm`dQ> {b. H$ {bE _ÐH$ Ed àHmeH बालाजी मुळे Ûmam bmoH$_V _r{S>`m àm. {b., ßbm°Q> H$. 192, 207, 208 E_. AmB. S>r. gr. BÊS>{ñQ´>`b E[a`m, ~Q>~moar, ZmJna _{ÐV Ed bmoH$_V ^dZ n. Odmhabmb Zhê$ _mJ, ZmJna _ àH$m{eV.
P.O.BOX NO. 230 R.N.I. No. 47101/89
XaÜd{Z : 0712-2423527 (7 bmBÝg) \°$g : 6618555
Email : gnmXH$s` : lsedit.ngp@lokmat.com
{dkmnZ : advt.ngp@lokmat.com {dVaU : circ.ngp@lokmat.com

इतिहास पर नजर 23 जुलाई

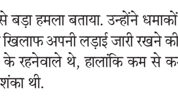

आज ही के दिन 2005 में मिस्त्र के शर्म-अल-शेख के रिजॉर्ट में हुए बम धमाकों में 88 लोग मारे गए थे. रात में हुए इन धमाकों में करीब 200 लोग घायल भी हुए थे. कुल तीन धमाके हुए थे, इनमें पहला पुराने बाजार में हुआ और बाकी दो एक रिजॉर्ट में हुए थे. मिस्त्र के तत्कालीन राष्ट्रपति होस्नी मुबारक ने इन्हें मिस्त्र के इतिहास का सबसे बड़ा हमला बताया. उन्होंने धमाकों वाले इलाकों का दौरा किया और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने की मंशा दोहराई. मारे गए लोगों में ज्यादातर मिस्त्र के रहनेवाले थे, हालांकि कम से कम 20 विदेशी नागरिकों के भी मारे जाने की आशंका थी.

- 1555-हुमायूं ने सरहिंद में सिकंदर सूरी पर विजय प्राप्त करने के बाद दिल्ली में प्रवेश किया.
- 1798-नेपोलियन ने मिस्त्र के अलेक्जेंड्रिया पर कब्जा किया.
- 1856-बाल गंगाधर तिलक का जन्म.
- 1877-अमेरिका के हवाई प्रांत में पहली टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइन का काम पूरा हुआ.
- 1906-चंद्रशेखर आजाद का जन्म.
- 2014-ट्रांस एशिया एयरवेज विमान के ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त होने से 44 लोगों की मौत हुई और 222 घायल हुए.

पाठकों के पत्र

सूचना के अधिकार का दुरुपयोग

वर्ष 2005 में देश में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ. यह कानून आम जनता के हित में साबित हुआ. कार्यालयीन कामकाज जल्दी निपटने लगे, कर्मचारी व अधिकारियों की जवाबदारी सुनिश्चित हुई, कार्यालयीन कामकाज में पारदर्शिता दिखने लगी. आवेदक को सही जानकारी निर्धारित समय में मिलने लगी, जिससे इस कानून को लेकर जनता में हर्ष जागा. लेकिन अब सूचना के इस अधिकार का दुरुपयोग भी देखने में आया है. इस नियम की आड़ में कुछ लोग अनाप-शनाप और बे-सिरपैर की जानकारी मांगते हैं. इससे कार्यालयीन कामकाज प्रभावित होता है. सूचना के अधिकार के जनक अन्ना हजारे ने भी इस बात पर चिंता जताई है. इस अधिनियम में अगर आवेदक को निर्धारित समय पर जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है. इसी तरह इस अधिनियम का दुरुपयोग करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए.

■ **संजय कुमार आर्य**, नागपुर

नाम भी बदल लिया!

मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने एक मित्र को सड़क पर जाते देखा; पीठ की तरफ से. तेजी से कदम बढ़ाए, जाकर उसकी पीठ ठोंकी और कहा, ''कहां खो गए थे अब्दुल. वर्षों बाद दिखाई पड़े.''

हास्य

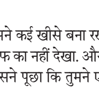

उस आदमी ने लौटकर, चौंक कर देखा. मुल्ला नसरुद्दीन ने भी उसे चौंक कर देखा और कहा, ''हद हो गई! कौन सी विपत्ति आई तुम पर? पिछली बार जब मिले थे तो ठिगने थे, मोटे थे और अब अचानक लंबे और दुबले हो गए. चेहरा भी बिल्कुल बदल डाला. दाढ़ी-मूंछ कब बढ़ा ली?''

उस आदमी ने कहा कि माफ करें, आप किसी और की भूल में होंगे. मेरा नाम अब्दुल नहीं है.

नसरुद्दीन ने दुबारा उसकी पीठ ठोंकी और कहा, ''प्यारे, तो नाम भी बदल लिया!''

इसी तरह एक बार नसरुद्दीन के रुपए खो गए. उसने कई खीसे बना रखे थे. सब खीसे उसने देख लिए सिर्फ उसने एक खीसा बायीं तरफ का नहीं देखा. और वह बड़ा परेशान था. नसरुद्दीन का मित्र भी उसके साथ था. उसने पूछा कि तुमने एक खीसा क्यों छोड़ दिया?

नसरुद्दीन ने कहा, ''वह मैं जानबूझ कर छोड़ रहा हूं. उससे कम से कम आशा तो है कि शायद वहां हो. सब तो देख लिए, निराश हो गया हूं. अब इसको मैं न देखूंगा; क्योंकि अगर उसमें भी न पाया तो पूरी आशा टूट जाएगी.''